(c) whenever an individual foreign missionary has come to the notice for undesirable activities, he has been asked to leave the country. Where there has been a violation of any law suitable action has been taken under the provisions of that law.

नवम्बर, 1969 में हुई राष्ट्रीय एकता परिषद् की बैठक में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों का प्रतिनिधित्व

*703. **श्री राम चरण** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय एकता परिषद् की 3 और 4 नवम्बर, 1969 को दिल्ली में हुई बैठक में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों का कोई प्रतिनिधि नहीं था ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि उक्त बैठक के समय कुछ हरिजन संगठनों ने बैठक में अपने प्रतिनिधित्व की मांग की थी ; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) इन तारीखों को राष्ट्रीय एकता परिषद् की कोई बैठक नहीं हुई । किन्तु साम्प्रदायिक हिंसा के विरुद्ध सभी राजनीतिक दलों द्वारा संयुक्त सामूहिक अभियान के लिए निश्चित उपायों का निर्णय करने के लिए स्थायी समिति के 16 अक्टूबर, 1969 के निर्णय के अनुसार राष्ट्रीय एकता परिषद द्वारा 3 और 4 नवम्बर, 1969 को एक सर्वदलीय सम्मेलन आयोजित किया गया । अत: उसके उद्देश्यों के अनुरूप सम्मेलन में आमन्त्रित व्यक्तियों का दो संगठनों को छोड़कर, निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य अथवा राष्ट्रीय दलों के रूप में मान्यता दिये गये दलों तक सीमित, मुस्लिम समुदाय के दृष्टिकोण को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने के लिए चयन किया गया था ।

(ग) यद्यपि सम्मेलन की मांगों का कोई औपचारिक मांग-पत्र पेश नहीं किया था तथापि एक हलका प्रदर्शन किया गया था ।

(घ) सर्वदलीय सम्मेलन द्वारा जारी किये गये बयान की एक प्रति सदन के सभा पटल पर रखी गयी है । [**ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या** LT 2431/69]

Setting up of a Police Commission to Modernise Police Force.

*704. SHRI LOBO PRABHU: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether in view of the last Police Commission having been set up 67 years ago, Government propose to set up a Police Commission to modernise the police force, in all the States, as it is proposed to do in Tamil Nadu;

(b) whether the Commission would consider the minimum qualification of High School for constables and a salary accordingly related, from savings which could be anticipated by reduction in numbers; and

(c) since the Centre is reported to be sharing in the cost of modernisation in Tamil Nadu, the reasons why it will not do so in all States, at least in respect of providing vehicles, including loans and grants for motor cycles to Station House Officers?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA): (a) and (b). Since police is a State subject, the respective State Governments consider the need and, if necessary, take steps to set up Police Commissions for going into matters relating to their police.